THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) to (d) Requests are received from time to time from different parts of the country including Arunachal Pradesh for setting up of MS/HSD Retail Outlet dealerships. Based on the feasibility surveys SEPPA, HOLONIL, PASI GHAT, BOLENG AND CHANOLANG have been included in the marketing plans for setting up of Retail Outlets by dealers to be selected through Oil Selection Board (North East).

Appointment of SKO dealerships in Arunachal Pradesh

3989. SHRINYODEKYONGGAM: Will trie Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government had received any proposal from the Government of Arunachal Pradesh for appointment of SKO dealership at JANG SEPPA, ZIROPOINT, DULLONGMUKH, SAGALEE, SIMPHU, TALIHA, DUM PORIZO, AHONOR, JENGTNG, MEBO, RUKSIN and BOLENG in Arunachal Pradesh:

(b) if so, what are the reasons of delay to appoint such dealership;

(c) whether feasibility survey has been carried out in all those places by the market ing division of IOC(ADD) located at Guwahati; and

(d) if so, the details thereof and the actiou taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPTAIN SATISH SHARMA): (a) to (u) Requests are received from time to time from different parts of the country including Arunachal Pradesh for setting up of SKOLDO dealerships. Based on feasibility surveys, SEPPAand TALIHA have been found feasible and LOIs to the persons selected through OSB have been issued for these two locations for setting up of SKOLDO dealerships.

पारगांव और देहरे स्टेशनों पर पार्सल सुविधाओं की अनुपलब्धता

3990. श्री गोविन्दराव आदिक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दौंड–मनमाड रेलमार्ग पर पड़ने वाले पारगांव एवं देहरे स्टेशनों पर पार्सल की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन स्टेशनों पर पेयजल और अन्य जनसुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार वहां पार्सल सुविधा, जनसुविधाएं और चौबीसों घण्टे की टिकट सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ): (क) से (ग) पारगांव और देहरे स्टेशन ठेकेदार परिचालित हाल्ट स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है क्योंकि वहां पर्याप्त पार्सल यातायात नहीं है। यातायात के मौजूदा स्तर के लिए इन स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधा सहित सुखसुविधाओं की व्यवस्था की गई है। केवल गाड़ी के समय के दौरान इन स्टेशनों पर टिकटें जारी करने की व्यवस्था उपलब्ध है। यातायात की मौजूदा मात्रा के लिए, इन हाल्ट स्टेशनों को बुकिंग के लिए चौबीसों घंटे खुला रखने का कोई औचित्य नहीं है।

Railway accident victims

3991. SHRI YERRA NARAYAN-SWAMY: Will the Minister of RAILWAY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that any of the recently acquired planes by the railways completed and mercy missions for railway accident victims;

(b) if so, the details of work or flights undertaken by the aeroplanes of railways for helping accident victims and arranging compassionate attention to such victims; and

(c) under what authority in the Railways administration the operation of these planes in functioning?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEFl: (a) Yes, Sir.

(b) On 14.6.94, the aircraft was flown from Delhi to Surat in connection with relief operations for the victims of an accident involving 2954 August Kranti Express and also for supervision of restoration of traffic.

रेलवे फाटकों पर ठपरि पुलों का निर्माण

3992. **श्री रामजीलाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में रेलवे ने कितने रेलफाटकों पर उपरि पुल (ओवरब्रिज) बनाए हैं और इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार दुर्घटनाप्रवरण रेल फाटकों पर उपरि पुल बनाने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या हिसार में डबल रेल–फाटक (ठण्डी सड़क) पर सरकार उपरि पुल बना रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे पुलों का निर्माण करने की ओर ध्यान देगी; यदि हां, तो ठण्डी सड़क हिसार में उपरि पुल के कब तक बन जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ): 55 ऊपरी/निचले पुलों पर रेलवे के भाग का काम पूरा हो गया है।

राज्य	ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या
1	2
असम	1
आन्ध्र प्रदेश	14
बिहार	1
दिल्ली	1
हरियाणा	1
कर्नाटक	5
महाराष्ट्र	1
मध्य प्रदेश	11
पंजाब	1
राजस्थान	1
तमिलनाडु	2
उत्तर प्रदेश	11
पश्चिम बंगाल	5
कुल	55

(ख) रेलें केवल उन्हीं व्यस्त समपारों पर जहां से होकर एक लाख या उससे अधिक गाड़ी वाहन यूनिट (यह वह संख्या है जिसे 24 घंटे में गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या के सड़क यातायात द्वारा गुणा करके प्राप्त किया जाता है) गुजरती है, के बदले ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण पर विचार करती है बशर्ते कि राज्य सरकार नियमानुसार अपने हिस्से की लागत वहन करने की विधिवत् सहमति सहित एक ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) किसी व्यस्त समपार के बदले में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की प्रणाली यह है कि राज्य सरकारें प्राथमिकता प्रदान करते हुए निर्माण कार्यों का प्रस्ताव करती हैं। तत्पश्चात् रेलवे मामलों की जांच करती है और उनमें से ऐसे कार्यों को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करती है, जिनके लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पूर्वापेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी है।

ठंडी सड़क हिसार में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण करने के बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Cash and carry scheme

3993. SHRI G. Y. KRISHNAN. Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the cash and carry scheme of the railways to move coal to thermal power station has come a cropper;

(b) if so, the reasons for the coal cash and carry scheme resulting in a flop;

(c) what is the amount outstanding against the National Thermal Power Corporation and various State Electricity Boards and how the Railways propose to recover the same, when Railways' own finances are in a critical shape; and

(d) whether Government would consider/ approaching the Ministry concerned with the grant of central assistance to the States to recover their dues from the allocated central plan aids?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. IAFFER SHARffiF): (a) and (b) No, Sir. Instructions for compulsory prepayment of freight for coal moved to certain Power Houses were issued as the dues to the Railways from these Power Houses were substantial. On receipt of representations from some of these undertakings that these instructions would result in disruption of power generation, they were withdrawn in their case.

(c) and (d) The amount outstanding against National Thermal Power Corporation is Rs. 539.30 crores and the dues outstanding